



छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक



■ मिशन शक्ति अभियान के तहत गुजनी पुलिस ने किया संवाद स्थापित

कानपुर। मिशन शक्ति अभियान के तहत शुक्रवार को गुजनी पुलिस ने हीरालाल इट्टनेशनल स्कूल में छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने छात्राओं को प्रदेश सरकार को और से जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। गुजनी थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि गंभीर स्थितियों से निपटने के लिए कभी भी हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। महिला सुरक्षा और स्वाचलन, महिला कल्याणकारी योजनाएँ व साफार अपराधों से बचने के लिए छात्र-छात्राओं से संवाद स्थापित किया। इसके अलावा बाल उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, गुड टच-बैड टच के बारे में विषय से जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि किसी साफार की साफार उग्गी होने पर तकलीफ प्रभाव से 1930 हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करें। उग्गी की तकलीफ सूचना देने पर खानों को फ्रीज किया जा सकता है। छात्राओं को बताया गया कि डेंगूज़ेड जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार ने बुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 जारी किया। जिसमें शिकायत करने पर पीड़ितों का नाम गोपनीय रखा जाता है। और समस्या के लिए त्वरित निस्तरण किया जाता है। बाल उत्पीड़न की रोकथाम के लिए चाल्झ डेल्प्लाइन नंबर 1098 सरकार ने जारी किया है। पुलिस अधिकारियों ने छात्र-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिस आपकी मदद के लिए तपत है।

नालों पर हुए अतिक्रमण को बुल्डोजर ने तोड़ा

कानपुर। शुक्रवार सुबह नगर निगम ने वीआईपी रोड पर परम्परा टेल पंप के पास अतिक्रमण अभियान चलाया। भारी पुलिस फोर्स के बीच नगर निगम के प्रवर्तन अतिक्रमण हटाना शुरू किया। बुल्डोजर ने नालों पर अतिक्रमण को तोड़ डाला। कारीब 1 किमी लंबाई में अभियान चलाया गया। बारिश के दौरान वीआईपी रोड पर जलभराव होता है। जलभराव से बचाव के लिए रोड किनारे बड़ी-बड़ी नालियां बनाई गई हैं, लेकिन लोगों ने घरों के सामने नालियों के ऊपर 10-10 की फीट तक के रैपने बाला डाला। इससे न तो नालियों की सफाई हो पा रही थी और न ही बारिश में जलभराव की समस्या से निजात मिल पा रही थी। बुल्डोजर भैंस घास वीआईपी रोड के किनारे बने नाली-नालियों पर अवैध अतिक्रमण पर चला। महापौर प्रमिला पाठेय ने भारी पुलिस फोर्स के बीच अभियान शुरू किया। बुल्डोजर देख कुछ लोगों ने बोला कि वे खुट तोड़ दें, लेकिन बुल्डोजर कार्रवाई जारी रही।

स्वतंत्र भारत

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।।

कोर्ट की फटकार

हिंसा और मानवीयता से जुड़े मापलों को गंभीरता से लेते हुए उनके विभिन्न पक्षों की गहराई से छानबीन करना इसलिए गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे वास्तविकता तक पहुंचने और सभी दंग से न्याय सुनिश्चित करने में मदद मिलती है लेकिन विभिन्न दृष्टियों से संवेदनशील और दिन के उजाले की तरह स्पष्ट घटनाओं की जांच को बिना बजाह नए मोड़ देने की कोशिशों पर स्वाभाविक रूप से सावल खड़े होते हैं इनके पीछे कभी मानवाधिकर उल्लंघन तो कभी न्याय की तह तक पहुंचने जैसे तरफ़ों को आधार बनाया जाता है जो वास्तव में आधारहीन होते हैं। नागरिकों और देश की सुरक्षा से सीधे रूप से संबंधित प्रकरणों पर इस दृष्टि से और भी अधिक सरकारी बरती जानी चाहिए। विभंगा यह है कि ऐसे मामलों में अवसर बेतुकी मार्ग उठाई जाती है जिनका मकसद पब्लिसिटी स्टंट या प्रचार पाने की भूमि होती है। पहलगाम नरसंहार ऐसी ही बेहद संवेदनशील घटना है। केंद्र इस पर व्यापक रूप से कई कदम उठा चुका है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसे लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका आई जिसमें पहलगाम की न्यायिक जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने याचिका देने वालों को फटकारते हुए जो दो अहम बातें कहीं, उसे प्रचार पाने को बैचैन व्यक्तियों/सगठनों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह कि जज आतंकी मामलों की जांच के विशेषज्ञ नहीं हैं। दूसरी अहम बात यह कि इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझते हुए अदालत में ऐसी कोई अपील न की जाए जिसमें सुरक्षा बलों का मनोबल गिरे। ऐसे विषय को न्यायिक क्षेत्र में लाया ही न जाए। कोर्ट के इन कथनों का मर्म समझना मुश्किल नहीं है और दोनों ही बातें तर्किक रूप से महत्वपूर्ण भी हैं। सोचने की बात यह है कि जिस घटना पर देश के प्रधानमंत्री बेहद गहराई से सक्रिय हों, सरकार लगातार दूरगामी निर्णय ले रही हो तथा आमतौर हर मामले पर खिलाफ रहने वाला विषय एकमत से उसका समर्थन कर रहा हो, तब किसी संदेह की गुंजाइश कहां बचती है। न्यायालय की फटकार वास्तव में देशहित को सबसे ऊपर रखने का साफ-साफ निर्देश भी है जिसका सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए।

हमारे महापुरुष

महापुरुष समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं जिनके आदर्शों पर चलकर जीवन के लक्ष्यों को सार्थकता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि वर्षों, दशकों और शताब्दियों के बाद भी ये प्राप्तिकर रहते हैं और हर नई पीढ़ी को इनका अनुकरण करने के लिए प्रेरित किया जाता है। हालांकि समाज में संक्रमण के दौर भी आते हैं और तब ये कोशिशें जरूरी होती हैं कि लोग इनसे भटकने न पाएं। लेकिन दिक्षित यह है कि आज के समय में लोग इसका महत्व नहीं समझते। नए-नए आकर्षणों में फंस कर वे उस गरसे पर चलना बेहर असर लेते हैं जिनकी किसी भी दृष्टि से उपयोगिता नहीं होती। ऐसे में जरूरी है कि महापुरुषों की स्मृति को पुनर्जीवित करके समाज में उनके प्रति जागरूकता पैदा की जाए। यह अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाम पर रखा है जिनके प्रभाव और प्रेरक शक्ति की पिछली सरकारों ने उपेक्षा की थी। यह सर्वविदित है कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान जाति के आधार महापुरुषों के नाम चुनकर केवल वोट बैंक की राजनीति होती थी और इनको केवल छुड़ाना कार्य किया जा सकता है। उसे विश्वास होता है, आखिरकार ही योगी को इमरजेंसी लगाई थी तो लोकसभा का कार्यकाल छह साल का कर दिया था। ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही भारत के संविधान का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जरूरत है कि भारत में विधिविका, कार्यालयिका और न्यायालयिका में से कोई सर्वोच्च संसद सर्वोच्च है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सर्वोच्चता का अतिक्रमण कर रहा है?

सबसे पहले इस वास्तविकता को समझ लेने की जर

